

⇒ CRAR (Capital to Risk-weighted Assets Ratio)

↓

बैंकों को अपनी जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों का रखे न्यूनतम अनुपात Core Capital के रूप में हमेशा बनाये रखना पड़ता है। इसे CRAR कहते हैं, इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी कहा जाता है।

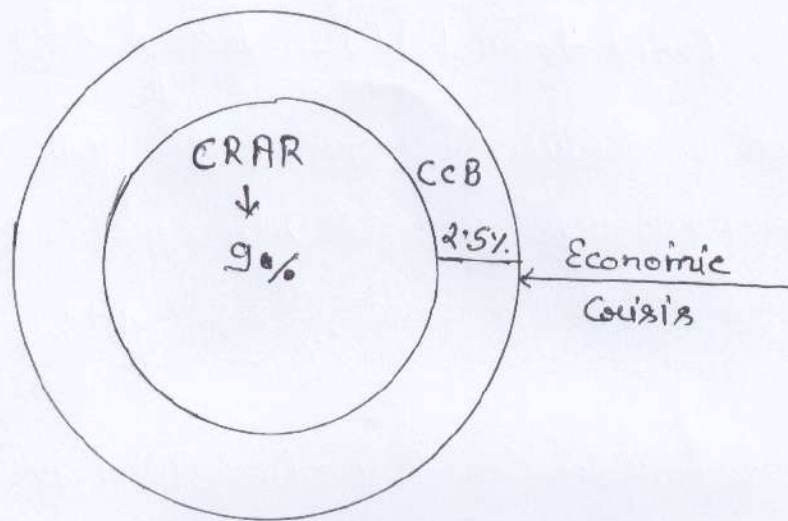
जोखिम भारित परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को सम्मिलित किया जाता है।

Core Capital बैंकों की ऐसी पूंजी होती है, जिसका प्रयोग वे किसी आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए आसानी से कर सकते हैं।

अन्य घटकों के मिलावा इसमें Equity/Common Equity को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है।

Basel-3 मानकों के अनुसार CRAR का न्यूनतम स्तर 8% होना चाहिए लेकिन भारत में इसका न्यूनतम स्तर 9% रखा गया है।

उपर्युक्त के मिलावा Equity के रूप में बैंकों को 4.5% का CCB (Capital Conservation Buffer) भी बनाये रखना पड़ता है। इसको सम्मिलित करते हुए Core Capital की कुल आवश्यकता 11.5% हो जाती है।



⇒ LCR (Liquidity Coverage Ratio)

⇓

बैंकों की संप्रणालिष्य तरलता के प्रबंधन से जुड़ा Basel-3 अनुपात निखण्य न्यूनतम स्तर 100% होता है।
इसके अन्तर्गत किसी दिन से आगे आने वाले 30 दिनों की समयावधि में on going basis पर तरलता प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाता है।

$$\text{सूत्र} \quad \frac{HQLA}{\text{आने वाले 30 दिनों में नष्ट या निवल बहिर्गमन}} \geq 100\%$$

∴ HQLA (High Quality Liquid Assets)

⇒ NSFR : Basel-3 Ratio से जुड़ा रण्य अनुपात

न्यूनतम स्तर : 100%

↳ Net Stable Funding Ratio

↓

रण्य वर्ष के लिए तरलता प्रबन्धन।

प्रश्न: MSF दर और NDTL का सम्बन्ध किस क्षेत्र से है?

Ans - बैंकिंग

प्रश्न: AOA, Peace Clause & SPS का सम्बन्ध किससे है?

Ans - कृषि

⇒ OMO (Open Market Operations)

↳ मरबुले बाजार की क्रियायें

↓

केन्द्रीय बैंक द्वारा G-Sec का छय-विक्रय करना।

↓

तरलता की मात्रा में परिवर्तन के लिए।

↓

↓

तरलता ↑

↓

G-Sec का छय

↓

तरलता ↓

↓

G-Sec का विक्रय

⇒ LTROs (Long Term Repo Operation)

- विशेष क्षेत्रों में तरलता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया था।

इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा 3 वर्ष तक के लिए रेपो दर के आधार पर बैंकों को धन उधार दिया गया था।

⇒ Microfinance

अर्थ- कम आय वाले लोगों को कम राशि की विभिन्न पुनार जी वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवाना।

इसे Banking for the Poor भी कहा जाता है।

ढावर (Coverage) - भारत में Microfinance के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।

- (i) Credit
- (ii) Pension & Insurance
- (iii) Remittance of funds
- (iv) Collection of thrift → मितव्ययता
Saving

Note - भारत में नाबार्ड के द्वारा SBLP (SHG Bank Linkage Programme) के माध्यम से 1992 में Microfinance की शुरुआत की गयी थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक करता है।

SBLP के अन्तर्गत बैंक निर्धन लोगों के स्वयं सहायता समूहों को त्वरोपगार की परिघोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है।

⇒ PSL (Priority Sector Lending)

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

UPSC-PT

↓

वाणिज्यिक बैंकों को अपने द्वारा दी जाने वाली कुल उधारियों का एक निश्चित भाग (40%) कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए आवंटित करना पड़ता है। इसे PSL कहते हैं। इसे Directed Lending भी कहते हैं।

इसमें निम्न क्षेत्रों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है—

- (i) Agriculture — 18%
- (ii) Exports
- (iii) BPL & Weaker Sections
- (iv) Housing
- (v) Education
- (vi) MSMEs
- (vii) Social Infra
- (viii) Renewable Energy

⇒ PSL $\frac{C}{T}$ (2016)
Certificates

→ स्कूल का मापदंड → ₹ 25 लाख

→ e-kubey पर मिलते हैं।

→ PSL का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर खरीदने पड़ते हैं।

